Original Article
ISSN (Online): 2582-7472

ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts
January-June 2023 4(1), 4762–4767

HAVANA CONFERENCE 2006: INDIA'S ROLE

हवाना सम्मेलन 2006: भारत की भूमिका

Dr. Vinod Kumar [1]

[1] Senior Academic Research, Postdoctorate, Ph.D., M.Phil., UGC NET & Extension Lecturer, Department of Political Science, Government College, Bahadurgarh, India

ABSTRACT

English: This paper evaluates the Havana Summit of the Non-Aligned Movement. India's role in the Non-Aligned Movement is assessed through this summit. This summit primarily represented a strong response to unipolar globalism. Havana was lavishly decorated for this grand event. This was the second time this country, with a population of 12 million, hosted this prestigious summit. The first Havana Summit was held in 1979. During this summit, the Cold War was at its peak. Movements against colonialism and imperialism were beginning to emerge; countries like Angola and Mozambique had gained independence. Fidel Castro sparked controversy in his speech at the United Nations by describing the former Soviet Union as a "natural partner" of the Non-Aligned Movement. However, circumstances have changed dramatically since then, although Fidel Castro remained steadfast in his ideological convictions and worldview until his final moments. However, on medical advice, he decided not to attend the 2006 Havana Summit and preferred to monitor the conference proceedings from his room at the Cuban Communist Party headquarters. During this time, he was recuperating from surgery. Regarding India's role, it played a significant and restrained role at the summit. Instead of harsh rhetoric, Indian delegates agreed to the final declaration approved by all heads of state and government.

Hindi: प्रस्तुत शोध पत्र गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के हवाना सम्मेलन का मूल्यांकन करता है। इस सम्मेलन के माध्यम से गुटनिरपेक्ष आन्दोलन में भारत की भूमिका का मूल्यांकन किया गया है। यह सम्मेलन मुख्य रूप से एकध्रुवीय विश्ववाद के प्रति अपनी सशक्त प्रतिक्रिया के साथ सामने आया। इस शिखर सम्मेलन के भव्य आयोजन के लिए हवाना को पूर्ण रूप से सजाया गया था। 1.2 करोड़ की आबादी वाले इस देश ने दूसरी बार इस प्रतिष्ठित शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। इससे पूर्व हवाना प्रथम सम्मेलन 1979 में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन के दौरान शीत युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद के विरुद्ध आन्दोलन उमरने लगे थे; अंगोला तथा मोजाम्बिक जैसे देशों को स्वतन्त्रता मिल गई थी। फिदेल कास्त्रो ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने भाषण में पूर्व सोवियत संघ को गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का "स्वाभाविक साथी" बताकर एक विवाद उत्पन्न कर दिया था। परन्तु उस समय की परिस्थितियां अब नाटकीय रूप से बदल गई हैं यद्यपि फिदेल कास्त्रो अपने अन्तिम क्षणों तक अपनी वैचारिक प्रतिबद्धताओं और विश्व के प्रति दृष्टिकोण के प्रति स्वतन्त्र अडिग रहे। हालांकि, चिकित्सकिय सलाह पर उन्होने हवाना सम्मेलन 2006 में शामिल न होने का फैसला किया और क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यालय स्थित अपने कमरे से ही सम्मेलन की कार्यवाही पर नजर रखना पसन्द किया। इस दौरान वे एक शल्यक्रिया के बाद स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। जहाँ तक भारत की भूमिका का संबंध है तो इस शिखर सम्मेलन में अपनी महत्वपूर्ण एवं संयमित भूमिका निभाई। भारतीय प्रतिनिधियों ने कठोर बयानबाजी की अपेक्षा सभी राष्ट्राध्यक्षों एवं राष्ट्रप्रमुखों द्वारा अनुमोदित अन्तिम घोषणा पत्र पर सहमति जताई।

Keywords: Confluence of Civilizations, Moderation, Terrorism, Preventive War, Hegemony, Human Rights, Unilateralism, Inclusive Renewal, सभ्यताओं का संगम, संयमित, आतंकवाद, निवारक युद्ध, वर्चस्व, मानवाधिकार, एकपक्षवाद, सम्मिलत नवीकरण

Corresponding Author

Dr. Vinod Kumar,
vinodkchahar@gmail.com

DOI
10.29121/shodhkosh.v4.i1.2023.6473

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Copyright: © 2023 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.

OPEN ACCESS

How to cite this article (APA): Kumar, V. (2023). Havana Conference 2006: India's Role. *ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts, 4*(1), 4762–4767. doi: 10.29121/shodhkosh.v4.i1.2023.6473

1. प्रस्तावना

गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के सभी सदस्यों ने क्यूबा गणराज्य की राज्यपरिषद और मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष फिदेल कास्त्रो की अध्यक्षता में सितम्बर 2006 को हवाना में आयोजित सम्मेलन में भाग लिया । राष्ट्राध्यों या शासनाध्यक्षों ने इस बात पर बल दिया कि वर्तमान वैश्विक परिदृष्य गुटनिरपेक्ष देशों के समक्ष शान्ति और सुरक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति, मानवाधिकारों और कानून के शासन के क्षेत्रों में चुनौतियां प्रस्तुत करता है। ये चुनौतियाँ बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुई हैं जोकि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के उद्देश्यों, सब सिद्धान्तों तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून तथा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर रही हैं अतः इन चुनौतियों और समस्याओं का समाधान करने के लिए एक समृद्ध विश्व, शान्तिपूर्ण, न्यायसंगत तथा समतामूलक विश्व व्यवस्था की स्थापना की जानी चाहिए ताकि विकासशील देशों के संसाधनों का विकास, आर्थिक एवं व्यापारिक सहयोग, अन्तर्राष्ट्रीय संबन्धों की प्रकृति और दिशा को निर्धारित किया जा सके। राष्ट्राध्यक्षों ने गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के संस्थापकों द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों फैसलों तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अन्तर्राष्ट्रीय कानून द्वारा निर्देशित प्रयासों का पालन करने के संकल्प को दौहराया। इस संदर्भ में क्यूबा के कार्यवाहक राष्ट्रपति राऊल कास्त्रो ने अपने अभिभाषण में सभी सदस्य देशों से आग्रह किया कि “सभी सदस्य राष्ट्रों को अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश को ध्यान में रखते हुए एकजुट होने की आवश्यकता है ताकि इस वैश्विक संगठन के सिद्धान्तों की रक्षा की जा सके जिसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। ये सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय कानून एवं संयुक्त राष्ट्र चार्टर में वर्णित है। “इन्होने विश्व प्रभुत्व स्थापित करने वाले दावों की निंदा की तथा बांडुंग सिद्धान्तों के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। साथ ही फिलिस्तीन के स्वतंत्र राज्य के अधिकार, सहराबी लोगों के आत्मनिर्णय तथा मालिवनास द्वीप पर अर्जेनटीना के दावे के प्रति भी समर्थन व्यक्त किया। इस शिखर सम्मेलन में भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के मौजूदा परिदृष्य को देखते हुए इसकी भूमिका के विषय पर चर्चा में भाग लेकर अपनी अग्रणीय भूमिका निभाई। भारत ने इस सम्मेलन के अन्तिम घोषणा पत्र को अपनाने का समर्थन किया तथा उच्च-स्तरीय अन्तर्राष्ट्रीय पदों के लिए भारतीय नागरिकों की सदस्यता की भी वकालत की यह शोध पत्र यूनिवर्सिटी हिंदी जर्नल, अंक-2, जुलाई-सितम्बर 2014 में भी प्रकाशित है।

2. हवाना सम्मेलन का मूल्यांकन

क्यूबा की राजधानी हवाना में 15 से 17 सितम्बर, 2006 को गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का चैदहवां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें “नैम’ के सभी 118 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। हवाना में फिदेल कास्त्रों की अस्वस्थता के कारण इस सम्मेलन की अध्यक्षता उनके भाई व क्यूबा के कार्यवाहक राष्ट्रपति राउल कास्त्रों ने की । सम्मेलन में हैती, सेंट किट्स और नेविस को नैम की नयी सदस्यता प्रदान की गई।’ राउल कास्त्रों ने अपने भाई की विशाल छवि के दायरे से बाहर निकलकर विश्व मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 31 जुलाई, 2006 को क्यूबा की बागडोर सौंपे जाने के बाद पहली बार इतने बड़े अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेते हुए 75 वर्षीय राउल कास्त्रों ने 118 सदस्यीय गुटनिरपेक्ष देशों के राष्ट्राध्यक्षों और प्रतिनिधियों से कहा कि यद्यपि अनके भाई की हालत में धीरे-धीरे और संतोषजनक सुधार हो रहा है फिर भी अच्छा होता यदि वे इस सम्मेलन में आप सभी का स्वागत करते । वहीं उन्होंने यह भी कहा कि इस सम्मेलन की तैयारियों एवं अन्य गतिविधियों के बारे में प्रत्येक विषय पर उनसे विस्तृत जानकारी और मार्गदर्शन लिया है।2

सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया तथा उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद और बदलते भू-राजनैतिक वातावरण में गुटनिरपेक्ष देशों के आन्दोलन को पुनः सक्रिय किये जाने की आवश्यकता को रेखांकित किया।3 आतंकवाद के मुद्दे पर भारत जैसे देशों की चिन्ताओं को ध्यान में रखते हुए अन्तिम दस्तावेज में कहा गया है कि लोगों में आतंक उत्पन्न करने वाले आपराधिक कृत्य किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराए जा सकते, भले ही उनका उद्देश्य कुछ भी हो, कहीं भी हो, जिस किसी के द्वारा किया गया हो और इसके लिए जो कोई भी उत्तरदायी हो। इसके अतिरिक्त भले ही उसे न्यायोचित ठहराने के लिए कोई भी दलील या कारण दिए जाएं। दस्तावेज में विभिन्न देशों से अन्तर्राष्ट्रीय और मानवीय कानूनों के अनुसार निर्धारित की गई प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने, आतंकवाद की साजिश करने वालों के विरुद्ध मामला चलाने और इन्हें प्रत्यर्पित करने एवं उन्हें दूसरे राज्यों के विरुद्ध आतंकवादी कार्यवाही करने के लिए आर्थिक या किसी अन्य तरह की सहायता उपलब्ध न कराने का आग्रह किया गया।4

भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने सम्बोधन में आतंकवाद के विरुद्ध दोहरे मानदण्डों के संदर्भ में सदस्य राष्ट्रों के समक्ष अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि “अगर वर्तमान परिस्थितियों में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन को अपनी प्रासंगिकता बनाए रखनी है तो इसे कट्टरवादी शक्तियों के विरुद्ध संगठित होना होगा । हम सभी सदस्य राष्ट्रों की ओर से यह संदेश आना चाहिए कि आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष करने एवं इसे जड़ से समाप्त करने के लिए हम सभी प्रतिबद्ध और संगठित हैं। आतंकी और चरमपंथी शक्तियां दुनियां का ध्यान गरीबी, अशिक्षा और बीमारी जैसी विश्व की अन्य महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर से हटा रही है जिसकी आज्ञा उन्हें नहीं दी जा सकती।5 अन्तिम दस्तावेज में कहा गया कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में गुटनिरपेक्ष देशो के सामने शान्ति, सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानवाधिकार, और कानून व्यवस्था की गम्भीर चुनौतियां हैं । सदस्य राष्ट्रों ने स्वीकार किया कि विश्व को शान्तिपूर्ण, समृद्ध एवं न्यायसंगत बनाने के लिए संगठन ने अनेक प्रयास किए हैं, परन्तु कट्टरपंथी शक्तियों ने सदैव इस प्रक्रिया में व्यवधान पैदा किए हैं । भारत ने सदस्य राष्ट्रों से आग्रह किया कि आतंकवाद सहित सभी अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं से निपटने के वैश्विक प्रयासों के संदर्भ में उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।6 सभ्यताओं के बीच टकराव के सिद्धान्त को नकारते हुए सिंह ने कहा कि “हम गुटनिरपेक्ष देशों ने विश्व को विचारधारात्मक आधारों पर गुटों में विभाजित करने के प्रयासों के विरुद्ध संघर्ष किया है। हमने जातीय विभाजन से परे शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व एवं उच्च मानवीय मूल्यों

को स्वीकार किया है। आज हम पुनः विश्व के समक्ष नकली संस्कृति और धार्मिक विभाजन के कारण बढ़ते हुए खतरों का सामना कर रहे हैं । गुटनिरपेक्ष आन्दोलन मानवता द्वारा स्वीकृत सभी धर्मों, सभी जातीय समूहों और समान विचारधाराओं को अपनाने वाले लोगों का समूह है जो आज पुनः लोगों में पारस्परिक समझ को बढ़ाने का कार्य करेगा । हमारा सहकारी विश्व अपने आप में 'सभ्यताओं के टकराव' के विरुद्ध है जबकि विश्व को हमारा यह संदेश होना चाहिए कि सभ्यताओं के समागम के लिए कार्य करना भी संभव है।7 प्रधानमंत्री ने पश्चिमी एशिया के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आज अगर कहीं विचारधाराओं का टकराव है तो वह पश्चिमी एशिया है। लेबनान में जिस प्रकार से युद्ध एवं भय का वातावरण छाया हुआ है उसने वहां के सामाजिक ताने-बाने को तहस-नहस कर दिया है। विभिन्न जातियों एवं धर्मों के लोगों में सद्भावना को बर्बरता में बदल दिया है। उन्होंने पश्चिमी एशिया की समस्या के समाधान के लिए अपना सुझाव देते हुए कहा कि, "मैं यह अनुशंसा करता हूं कि हमें पश्चिमी एशिया में एक उच्च स्तरीय समूह की स्थापना करनी चाहिए जो इस क्षेत्र में आपसी समझ बढ़ाने और व्यापक शान्ति के लिए पहले से सहमत रोडमैप के क्रियान्वयन में भूमिका निभा सके। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को इस समस्या के समाधान के लिए पूर्णरूप से अपना उत्तरदायित्व निभाना चाहिए ताकि एक लम्बे समय से फिलिस्तीनी जनता जो दुख सहन कर रही है उनका अन्त हो सके।8

सम्मेलन के दौरान ईरान को अपने विवादास्पद परमाणु कार्यक्रम के पक्ष में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का व्यापक समर्थन मिला। उन्होंने इस बात पर सहमति प्रकट की कि सभी देशों को शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु उर्जा के विकास, उत्पादन और इस्तेमाल का मूल अधिकार है तथा इस संदर्भ में कोई भी विवाद केवल वार्ता के माध्यम से ही सुलझाया जा सकता है । सदस्य राष्ट्रों ने इस ओर भी ध्यान दिलाया कि अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण ने यह पाया है कि ईरान द्वारा घोषित सभी परमाणु सामग्री परखी गई है तथा शान्तिपूर्ण प्रयोजन के लिए इस्तेमाल में लाए जा रहे किसी भी परमाणु संस्थान के विरुद्ध आक्रमण अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है । साथ ही इन नेताओं ने ईरान से अनुरोध किया कि वह आई.ई.ए.इ.ए. के साथ पूरी तरह सहयोग करना जारी रखे।8 ईरान मुद्दे पर भारत ने गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का समर्थन किया और अपने पूर्व वक्तव्य, जो कि मई 2006 में दिया गया था, पर अपनी प्रतिबद्धता जताई। सिंह ने स्पष्ट किया कि यदि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के संदर्भ में कोई संदेह है तो बाध्यकारी साधनों की अपेक्षा संवाद और विचार विमर्श के माध्यम से इसका समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि, "मैने पहले भी कई अवसरों पर कहा है कि ईरान को एन.पी.टी. का सदस्य होने के नाते इसके सभी अनुदेशों का पालन करना चाहिए।"10 इसके अतिरिक्त सम्मेलन में एकपक्षवाद और अन्तर्राष्ट्रीय संबन्धों में प्रभुत्व स्थापित करने के प्रयासों और विभिन्न देशों के राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति में व्यवधान उत्पन्न करने की प्रवृति की भी निन्दा की गई।11 92 पृष्ठीय राजनीतिक घोषणा-पत्र में विस्तृत रूप से अमेरिका की आधिपत्यपूर्ण प्रवृतियों का विरोध करते हुए कहा गया कि वर्तमान समय में बहुपक्षवाद को बढावा दिया जाना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धान्तों को मजबूत बनाना चाहिए क्योंकि ऐसा करके ही आन्दोलन को पुनर्जीवित किया जा सकता है। राउल कास्त्रो ने अपने अध्यक्षीय भाषण में स्पष्ट किया कि जिन सिद्धान्तों की सुरक्षा के लिए सदस्य राष्ट्रों ने संगठित होकर 'नैम' की स्थापना की थी, वह निश्चित रूप से समय की मांग थी, ये सिद्धान्त संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी स्वीकार किए गए थे परन्तु वर्तमान समय में असंख्य सदस्य राष्ट्र अमान्य आक्रमणकारी गतिविधियों से प्रभावित हो रहे हैं और ऐसा सामरिक संसाधनों को प्राप्त करने की लालसा के कारण हो रहा है जिसके फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है । उन्होंने 'निवारक युद्धों के सिद्धान्त' का विरोध करते हुए कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष तथा लोकतंत्र की रक्षा तो केवल बहाना है । अतः गुटनिरपेक्ष आन्दोलन को बाण्डुंग (1955) में निर्धारित सभी सिद्धान्तों की रक्षा के लिए मिलकर कार्य करना होगा।12 आन्दोलन के निवर्तमान अध्यक्ष और मलेशिया के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला अहमद बदावी ने सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि गुटनिरपेक्ष देशों का संघर्ष किसी देश विशेष के विरुद्ध नहीं है बल्कि अन्याय, और आर्थिक शोषण, व्यापारिक असमानता, बड़ी शक्तियों का वर्चस्व, जनसंहारक हथियारों का खतरा, हस्तक्षेप, मानवाधिकारों का उल्लंघन तथा सामाजिक और आर्थिक शोषण के विरुद्ध है।13 यद्यपि अमेरिका विरोधी इस माहौल में वस्तुस्थिति को देखते हुए अमेरिका से बढ़ रही निकटता को रेखांकित नहीं किया और न ही भारत-अमेरिका परमाणु संधि के संदर्भ में कोई टिप्पणी की क्योंकि अनेक गुटनिरपेक्ष राष्ट्र जैसे क्यूबा, फिलिस्तीन, लेबनान आदि अमेरिका की दोहरी नीतियों एवं हस्तक्षेप से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। तथापि भारत ने दक्षिण के सभी गरीब राष्ट्रों को सुझाव दिया कि उन्हें विकसित राष्ट्रों के विरोध की अपेक्षा अपने राष्ट्रीय हितों को पूर्ण करने के लिए पारस्परिक सहयोग करना चाहिए।।4 सिंह ने जवाहर लाल नेहरू के भाषण का उद्धरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि

"गुटनिरपेक्षता कार्य करने की स्वतन्त्रता है जो कि स्वतंत्रता का हिस्सा है।" उन्होंने हमें मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने को कहा था जो पूरी आजादी और बिना किसी पूर्व अनुमान और पक्षपात के हो । यही दृष्टि हमें आने वाले वर्षों में नयी दिशा प्रदान करती रहेगी।15

घोषणा पत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ की पुनर्संरचना एवं सुरक्षा परिषद के विस्तार की मांग की गई । संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव की अन्नान ने इस संदर्भ में कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ एवं विकासशील देशों की रक्षा के लिए सुरक्षा परिषद में सुधार आवश्यक है, संकीर्ण स्वार्थों पर आधारित कार्यवाहियों से संयुक्त राष्ट्र संघ की वैद्यता पर प्रश्न चिन्ह लगेगा और लोकतंत्र की भावना कमजोर होगी।16 भारत ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार विशेषकर सुरक्षा परिषद में विस्तार के लिए मांग की ताकि विकासशील राष्ट्रों को भी इसमें प्रतिनिधित्व मिल सके और इस संस्था को और अधिक लोकतान्त्रिक, प्रतिनिधि, उत्तरदायी और प्रभावशील बनाया जा सके।17 सिंह ने अपने भाषण में कहा कि "संयुक्त राष्ट्र संघ ने अतीत में अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बदलने में अपनी रचनात्मक और नेतृत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा ऐसा ही इसे पुनः करना होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार बदलती हुई परिस्थितियों की मांग है । विकासशील देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता मिलनी ही चाहिए। हमें वैश्विक शासन की प्रक्रिया में लोकतान्त्रिकरण को बढ़ावा देने के लिए विकसित राष्ट्रों से निश्चित रूप से हाथ मिलाना चाहिए, ताकि एक नई विश्व व्यवस्था स्थापित हो सके जो कानून के शासन, न्याय और समानता पर आधारित हो।18 सम्मेलन में दूसरा महत्वपूर्ण पहलू निरस्त्रीकरण से सम्बन्धित था जिसके द्वारा सभी सदस्य राष्ट्रों ने परमाणु मुक्त विश्व बनाने पर बल दिया। सिंह ने इस संबंध में कहा कि "1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में परमाणु निरस्त्रीकरण के संबन्ध में एक विस्तृत कार्य

योजना प्रस्तुत की थी। मेरा मानना है कि अब समय आ गया है जब 'नैम' को पुनः परमाणु निरस्त्रीकरण में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। भारत ने परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए एक व्यापक प्रारूप तैयार किया है जिसे इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन में दस्तावेज के रूप में प्रचारित किया जाएगा। हम सभी सदस्य राष्ट्रों को सार्वभौमिक परमाणु निरस्त्रीकरण और विश्व को परमाणु हथियारों से मुक्त बनाए जाने के प्रयासों में आमंत्रित करते हैं।19 उन्होंने 'नैम' के नेताओं से मानव जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए ऊर्जा सुरक्षा पर सहयोग करने के लिए अनुग्रह किया तथा एक कार्य समूह के गठन का भी सुझाव दिया जो भविष्य की ऊर्जा सम्बंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए कार्य योजना तैयार करे।20 अफीकी देशों के साथ सहयोग के लिए उन्होंने स्पष्ट किया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा और गुटनिरपेक्ष आन्दोलन में अफीकी देशों की सबसे अधिक भागीदारी है। अतः हमारा भविष्य अफीकी लोगों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। मेरा मानना है कि 'नैम' के लिए अफीकी देशों में विकास कार्यों के लिए प्रमुख पहल करने का यह अच्छा अवसर है। उन्होंने कहा कि "नैम द्वारा इस प्रकार की पहल कृषि विकास एवं मानवीय संसाधनों के विकास में अत्यधिक सहायक सिद्ध होगी । आन्दोलन अफीकी संघ के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए एक कार्यप्रणाली स्थापित करने के लिए आगे आएगा ताकि अफ्रीका में पूंजी निवेश किया जा सके। हम इस दिशा में ऐसे अन्य सदस्य राष्ट्रों के साथ कार्य करने के इच्छुक होंगे जो अफ्रीका में इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में सहयोग करेंगे।21 सिंह ने आन्दोलन को पुनः सक्रिय करने के लिए भी सदस्य राष्ट्रों से अनुरोध किया । उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि हम इस आन्दोलन को पुनर्जीवित करना चाहते हैं तो हमें इस आन्दोलन से यह संकल्प लेना होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों का सफलतापूर्वक समाधान करने के लिए आगे आयेंगे, चाहे ये आतंकवाद, सार्वभौमिक महामारी, ऊर्जा सुरक्षा तथा पर्यावरण से सम्बन्धित हो । उन्होंने गांधी जी के संदेश का हवाला देते हुए कहा कि "एक समूह के रूप में हमने अतिवाद की अवहेलना की है । हमें शान्ति के दूत गांधी जी का संदेश फैलाना चाहिए तभी हमारी आवाज तर्कयुक्त, शान्ति तथा न्याय से परिपूर्ण होगी। अगर ऐसी आवाज आधी से ज्यादा दुनिया की है तो यह बरकरार रहेगी तथा सर्वत्र वैलेगी और यह हमारे संगठन का भविष्य निर्धारित करेगी।"22 आर्थिक विषयों पर उन्होंने भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि हम सभी परस्पर निर्भरता के संसार में जी रहे हैं । राष्ट्रों की इस अन्तः निर्भरता को नियंत्रित एवं न्यायसंगत बनाने के मार्ग में चुनौतियां निश्चित रूप से हैं। वैविकरण के इस बढ़ते हुए माहौल में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सीमाएं अप्रासंगिक एवं छोटी हो रही है। हमारी समस्याएं वैश्विक हैं, इसलिए निदान भी उसी के अनुरूप होना चाहिए।23 सिंह ने 'सम्मिलित वैश्वीकरण' के लिए सदस्य राष्ट्रों से एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा, "आर्थिक विषयों पर बाइबिल के कथन 'जिसके पास जो है उसे ही मिलेगा' का बहुत ही ज्यादा महत्व है। वैश्वीकरण का लाभ सभी को समान रूप से मिलना चाहिए अन्यथा संपूर्ण विश्व की चुनौतियों के प्रति जवाब असमान और पक्षपातपूर्ण रहेगा।"24 इस संदर्भ में सभी राष्ट्रों ने अपनी सहमति व्यक्त की।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ और भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आतंकवाद की विभीषिका से निपटने तथा जम्मू कश्मीर सहित सभी मामलों का समाधान निकालने के लिए शान्ति प्रक्रिया जारी रखने पर सहमति जताई। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए 'दोनों नेताओं ने 6 जनवरी, 2004, 24 सितम्बर, 2004, 18 अप्रैल, 2005 और 14 सितम्बर, 2005 को हुई संयुक्त वार्ताओं को पुनः क्रियान्वित करने का निश्चय किया। दोनों नेताओं ने यह भी स्वीकार किया कि शान्ति प्रक्रिया बरकरार रहनी चाहिए क्योंकि इसकी सफलता ही भविष्य में दोनों देशों के साथ संपूर्ण क्षेत्र के लिए अहमियत रखती है। इस विषय पर उन्होंने अपने विदेश सचिवों को इस दिशा में द्विपक्षीय वार्ता को आरम्भ करने के निर्देश दिए।25 मुंबई में हुए विस्र्लोटों के बाद पाकिस्तान से शान्ति प्रक्रिया के तहत विदेश सचिव वार्ता स्थगित कर दी गई थी । परन्तु हवाना सम्मेलन में दोनों नेताओं ने आतंकवाद से संबन्धित हर प्रकार की कार्यवाही का विरोध किया और आतंकवाद के विरुद्ध चरणबद्ध तरीके से सम्मिलित प्रयास करने का आह्वान किया।26 दोनों नेताओं की द्विपक्षीय वार्ता के पश्चात जारी संयुक्त ब्यान में आतंकवाद की पहचान एवं आतंकवाद विरोधी जांच के लिए संस्थागत तंत्र की स्थापना के संदर्भ में पूछे गए सवालों के जवाब में विदेश सचिव शिवशंकर मेनन ने कहा कि भारत व पाकिस्तान के बीच आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग का ढांचा तैयार करने पर जो सहमति बनी है उसके अनुसार आतंकवाद की जांच और इसे रोकने के उपाय किए जायेंगे। मेनन ने इस बात से स्पष्ट इन्कार किया कि संयुक्त संस्थागत तंत्र की स्थापना के निर्णय से पाकिस्तान के प्रति भारत के दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तन आया है, अपितु कहा कि आतंकवाद पर हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है। पाकिस्तान में ऐसे तत्व विद्यमान हैं जो भारत में आतंकवाद के लिए उत्तरदायी हैं। उन्होंने कहा कि वास्तविकता यह है कि आतंकवाद पाकिस्तान के लिए भी उसी तरह एक खतरा है जिस तरह भारत के लिए। दोनों संयुक्त रूप से इस समस्या से निपटने का प्रयास करेंगे और यह तंत्र इस दिशा में एक सराहनीय कदम साबित होगा।27 अतः गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के मंच से आतंकवाद के विरुद्ध संस्थाबद्ध तरीके से सम्मिलित प्रयास करने के लिए पाकिस्तान को सहमत कराना निश्चित रूप से भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत रही।

भारतीय प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति मुशर्रफ के अतिरिक्त कई अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों से भेंट की और उनसे विभिन्न द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा की । इनमें श्रीलंका के राष्ट्रपति महेन्द्र राजपक्षे, ईरान के राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद, मारिशस के प्रधानमंत्री नवीन चन्द्र रामगुलाम, क्यूबा के कार्यवाहक राष्ट्रपति राउल कास्त्रों, वेनेजुएला के राष्ट्रपति हुगो शावेज, नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली, मलोशिया के प्रधानमंत्री अहमद बदवई और मंगोलिया के राष्ट्रपति नाम्बारिन एखबयार शामिल थे।28 राजपक्षे के साथ भारत के प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के ताजा घटनाक्रम पर चर्चा की और आशा व्यक्त की कि वहां की जातीय समस्या का समाधान उचित वार्ता प्रक्रिया के माध्यम से होगा। इसके लिए भारत सदैव अपना योगदान देने को प्रतिबद्ध है। इस संदर्भ में राजपक्षे ने भारत के योगदान की सराहना की । मारिशस के प्रधानमंत्री नवीनचन्द्र रामगुलाम से बातचीत में मनमोहन सिंह ने मारिशस को भारत का 'चेचेरा भाई' बताया और कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय सम्बन्ध काफी सद्भावनापूर्ण रहे हैं और अब भी दोनों देशों के सम्बन्धों में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है । नेपाल के उप प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने भी मनमोहन सिंह से मुलाकात की और नेपाल में लोकतंत्र बहाली के बाद के हालात पर चर्चा की । सिंह ने नेपाल को भारत का एक प्रमुख पड़ौसी देश बताया। मंगोलियाई राष्ट्रपति नाम्बरिन एखबयार से भेंट के दौरान दोनों देशों के सदियों पुराने और परम्परागत सम्बन्धों को याद किया गया और कहा गया कि दोनों देशों में व्यापार बढ़ाने की

पर्याप्त संभावनाएं हैं।29 इसके अतिरिक्त सिंह और अहमदी नेजाद ने प्रस्तावित ईरान-पाकिस्तान भारत गैस पाइपलाइन परियोजना की प्रगति के अतिरिक्त अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। दोनों पक्षों ने इस परियोजना को आगे बढ़ाने में रूचि दिखाई और इसके तकनीकि पहलुओं को शीघ्र ही अन्तिम रूप देने का निर्णय लिया । वेनेजुएला के राष्ट्रपति हुगो शावेज से मुलाकात के दौरान दोनों देशों ने आर्थिक संबंधों विशेषकर उर्जा के क्षेत्र में चर्चा की। शावेज ने दक्षिण आयोग के प्रतिवेदन को, जो कि 1980 में मनमोहन सिंह द्वारा दक्षिण आयोग का सचिव होने के नाते तैयार किया था, को व्यापक रूप से उद्धृत किया। उन्होंने भारत से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता के लिए समर्थन मांगा। भारत ने स्पष्ट किया कि वह वेनजुएला के पक्ष में अपना वोट देगा। शावेज ने केरल और पश्चिमी बंगाल में निजी यात्रा के लिए इच्छा व्यक्त की।30 मनमोहन सिंह ने गुटनिरपेक्ष आन्दोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले क्यूबा के अस्वस्थ राष्ट्रपति देलि कास्त्रो से साम्यवादी दल के कार्यालय में भेंट की और उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को अपने-अपने देश की राजनीति, आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों से अवगत कराया । कास्त्रो ने ऐतिहासिक क्षणों को स्मरण करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू और इन्दिरा गांधी के साथ मधुर सम्बन्धों की याद ताजा की। उन्होंने मनमोहन सिंह से भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में पूछा और ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में चर्चा की । उन्होंने सिंह को बताया कि एक विकासशील देश होने के नाते क्यूबा आर्थिक रूप से भले ही धनी न हो परन्तु वह मानव संसाधन के क्षेत्र में काफी समृद्ध हैं और दोनों देशों के मध्य सहयोग की अपूर्व संभावनाएं हैं।31 उपरोक्त संदर्भों में भारत ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इस सम्पूर्ण विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि 1961 में 25 राष्ट्रों की भागीदारी से बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का पहला औपचारिक सम्मेलन सम्पन्न हुआ था । तब से लेकर आज तक भारत ने इस आन्दोलन के प्रत्येक सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, चाहे वह रंगभेद की नीति का विरोध हो, साम्राज्यवाद, भुखमरी, दक्षिण-दक्षिण संवाद, राष्ट्रों की आजादी का मामला, आतंकवाद, निरस्त्रीकरण एवं अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा, नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था आदि भारत के लिए अहम मुद्दे रहे हैं। शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद विश्व के समक्ष भी अनेक चुनौतियां थी जिनमें सबसे प्रमुख चुनौती यह थी कि बदलते हुए विश्व परिदृष्य में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन अपनी वैद्यता को किस प्रकार बनाए रखे ? क्योंकि शीतयुद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व राजनीति में अनेक परिवर्तन आये । इस कारण आन्दोलन पर इन घटनाओं का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था । इसके सदस्य राष्ट्र इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न उठाने लगे और कहा जाने लगा कि अब इस आन्दोलन को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया चाहिए । परन्तु भारत ने इस बात पर जोर दिया कि इस आन्दोलन को बदलते हुए परिवेश में अपनी प्राथमिकताओं को बदलना चाहिए । भारत का मानना है कि जब तक तीसरी दुनियां के देशों की मूलभूत समस्यायें बनी रहेंगी इस संगठन का महत्व भी बना रहेगा । भारत काफी हद तक अपने प्रभाव के द्वारा आन्दोलन को संरक्षित रखने में सफल रहा है । परन्तु अब उसे सदस्य राष्ट्रों का सुनियोजित रणनीति द्वारा मार्गदर्शन करना है ताकि वे अपनी समस्याओं से निजात पा सके। और ऐसा तभी संभव होगा जब भारत सभी देशों के साथ मैत्री कायम करते हुए बहुध्रुवीय विश्व की परिकल्पना में सहयोग देगा ।

संदर्भ

एशियन न्यूज डाइजेस्ट, वॉ॰ 7नं. 42, 7-13 अक्टूबर, 2006, पृ. 5663.
"गुटनिरपेक्ष मंच से राउल ने अमेरिका पर साधा निशाना," राष्ट्रीय सहारा, नई दिल्ली, 17 सितम्बर 2006.
ए॰पी॰ गरनमा, "गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलनः कास्त्रों का आखिरी जलसा" इंडिया टुडे, अंक 48, 20 सितम्बर, 2006, पृ. 43.
वी॰एस॰ चन्द्रशेखर, "नैम इन्डार्सज इंडियाज स्टैण्ड ऑन टैरर" द ट्रिब्यून, नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2006.
द टाइम्स ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2006.
"नैम'स प्रेस्पेक्टिव ऑन टेरेरिज्म," न्यूज फॉम नान-अलाईंड वल्ड" वॉ॰ 27, नं॰ 14, 2 जनवरी, 2007, पृ. 6-7.
"नैम शुड नॉट बी ऐम्बिग्युअॅस ऑन टेरेरिज्मः मनमोहन", द हिन्दू, नई दिल्ली, सितम्बर 2006.
भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा चैदहवें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन ;हवाना, 15 सितम्बर 2006द्ध में दिया गया भाषण, स्ट्रेटेजिक डाइजेस्ट, वॉ॰ 36, न. 10, अक्टुबर, 2006, पृ. 1297.
चन्द्रशेखर, संख्या 4.
द हिन्दू, नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2006.
रोनोजॉय सैन, "अमेरिकन ग्रेफिटी," टाइम्स ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली, 18 सितम्बर 2006.
जॉन चेरियन, "रिटर्न ऑफ नैम" फ्रंटलाइन, वॉ॰ 23 नं॰ 19, सितम्बर- अक्टूबर, 2006, पृ.
सहारा टाइम्स, नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2006.
"फोरटीन नैम समिटः ए रिव्यू," मैनस्ट्रीम वॉ॰ 44, नं॰ 42, 6-12 अक्टूबर, 2006, पृ. 14.
सी॰पी॰ भाम्भरी, "नॉन अलाईनमेंट इन द चेनिं्जग कान्टेक्सट आफॅ ट्वैन्टी फस्र्ट सैन्चुरी, " इंडिया क्वाटरली, वॉ॰ 72, नं. 3, जुलाई-सितम्बर, 2006 पृ. 100.
चेरियन, संख्या 12, पृ. 6.
"नैम टोटली अपोज्ड टू टैरेरिज्मः डिक्लेरेशन" द हिन्दू, नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2006.
सिंह, संख्या 8.

नवीन कपूर, “नैम मस्ट कोकस ऑन टेर्र सेज पीएम“ द ट्रिब्यून, नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2006.
एन. रवि, “इंडिया सीज नैमस रोल एज वन ऑफ “मॉडरेशन, हार्मोनी एण्ड रीजन“ द हिन्दू, नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2006.
प्रथा एस० घोष, “बियोन्ड द रेट्रिक, “ पन्टलाईन, वॉ॰ 23, नं० 19 सितम्बर अक्टूबर, 2006, पृ. 9.
द हिन्दू, नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2006.
सी०पी० भाम्भरी, “फॉरेन पालिसी फेसिज ए टफ टेस्ट,“ सहारा टाइम्स, नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2006.
घोष, संख्या 21, पृ. 8.
भारत पाकिस्तान संयुक्त वक्तव्यः हवाना, 16 सितम्बर 2006, स्ट्रेटेजिक डाइजेस्ट, वॉ॰ 36, नं. 10 अक्टूबर, 2006, पृ. 1298.
“हवाना स्टेटमैंट: न्यू मैकेनिज्म फॉर पीस, इकॉनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, वॉ० 41 नं. 39, सितम्बर 2006, पृ. 4096.
एन. रवि, “एग्रीमैन्ट ऑन एन्टी-टैरर मैकेनिज्म हैल्पड: मेनन “द हिन्दू, नई दिल्ली, 18 सितम्बर 2006.
इंडियन एक्सप्रैस, नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2006.
सहारा टाइम्स, नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2006.
जॉन चेरियन, “साइडलाईन समिट्स“ फन्टलाईन, वॉ॰ 23, नं० 19 सितम्बर अक्टूबर 6, 2006, पृ. 12.
एन॰ रवि, “कास्त्रो नास्टोल्जिक इन हिज मिटिंग विद मनमोहन“ द हिन्दू, नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2006.